९ बदलता जीवन : भाग १

अभी तक हमने वर्ष १९६१ से वर्ष २००० तक के कालखंड का अध्ययन किया। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में परिवर्तन की गति तीव्र है। मानव जीवन तेजी से बदल रहा है। पहले हम जिन बातों की कल्पना भी नहीं कर सके; वे बातें अब वास्तविकता में उतरी हैं। प्राचीन एवं मध्ययुग में धर्म मनुष्य की एक महत्त्वपूर्ण पहचान थी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ज्यू (यहूदी) आदि धर्मों के सामने आधुनिकीकरण ने चुनौतियाँ खड़ी की हैं। हमारी पारंपरिक विचारधारा में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह परिवर्तन भारतीय संविधान के माध्यम से किया है।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

हमारे संविधान के अनुसार कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं तथा धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्रित तथा संगठित होने का, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने-फिरने का, रहने का तथा स्थायी तौर पर रहने का, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी स्वयं की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संवर्धन करने का अधिकार है।

संविधान के इन प्रावधानों के कारण जातिव्यवस्था के ढाँचे पर आघात हुआ है। वंशपरंपरागत व्यवसाय की कल्पना कालबाह्य होने में सहायता मिली। जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। इन प्रावधानों का परिणाम यंत्रों पर भी किस प्रकार हुआ; यह निम्नलिखित चौखट से समझ में आ जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

ब्रिटिशों के शासनकाल में रेल डिब्बों के चार प्रकार थे। फर्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड क्लास जैसे चार वर्ग थे। तीसरे वर्ग के यात्रियों के लिए मामूली-सी सुविधा और उन यात्रियों की ओर देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण; इस कारण यह वर्ग मानो भारतीय समाज व्यवस्था का प्रतीक ही बन चुका था। १९७८ के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री मधु दंडवते ने तीसरी श्रेणी की व्यवस्था समाप्त कर दी। बाद में पुणे-मुंबई के बीच 'सिंहगढ़ एक्सप्रेस', मुंबई-कोलकाता के बीच 'गीतांजलि एक्सप्रेस' ये वर्गरहित गाड़ियाँ प्रारंभ हुईं।

उपरोक्त प्रावधानों के कारण समाज में छोटे-बड़े परिवर्तन धीरे-धीरे होने लगे। अब होटल में सभी के लिए प्रवेश खुला है। धर्म, वंश, जाति, लिंग इन कारणों से प्रवेश नकारा नहीं जाएगा; ऐसी तख्तियाँ होटलों में हम देखते हैं।

पहले राजसत्ता के विरुद्ध विचार प्रकट करने की कुछ मर्यादाएँ थीं। अब भारतीय नागरिक समाचारपत्र अथवा भाषण और अन्य माध्यमों द्वारा सरकार के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। हमें अमान्य लगने वाली बातें हम बोल सकते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में हुआ है।

परिवार संस्था : स्वातंत्र्यपूर्व कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी। 'संयुक्त परिवार पद्धति का देश' के रूप में भारत संसार भर में पहचाना जाता

था। वैश्वीकरण की लहर में विभक्त परिवार पद्धति को बढ़ावा मिला है।

समाज कल्याण : कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है; यह भारत के संविधान में उल्लिखित है। ऐसा उल्लेख करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवा देना समाजकल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्पसंख्यकों तक विकास के अवसर पहुँचना आवश्यक है। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए भारत सरकार ने १४ जून १९६४ को समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया। इस मंत्रालय के अंतर्गत पोषण और बालविकास, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी की गई है।

अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ : वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार देश में २२% लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के थे। इन सबके लिए कानून बनाकर शैक्षिक छात्रवृत्ति एवं प्रतिनिधित्व देकर संसद, राज्य विधि मंडल और सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य : प्रथम कर्तव्य के रूप में सरकार भारतीय जनता के रहन-सहन का स्तर बढ़ाए, उनका पोषण करें एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधारे; ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय इस संदर्भ में राज्य सरकार की सहायता करता है। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, आदिवासियों एवं गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप की स्वास्थ्य सेवाएँ तथा चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवा देने का उद्देश्य था। स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत में एलोपैथी, यूनानी, होमियोपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को मान्यता देकर नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने का प्रयत्न शुरू किया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के कारण भारतीयों का जीवन अधिकाधिक चिंतारहित होने में सहायता मिली। वर्ष १९६२ में तमिलनाडु के वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉ. एन. गोपीनाथ के नेतृत्व में भारत में 'ओपन हार्ट सर्जरी' सफलतापूर्वक की गई। इस कारण ऐसे उपचारों के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं रही।

'जयपुर फुट' की खोज से भारत के दिव्यांगों का जीवन बदल गया। १९६८ से पूर्व एकाध व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होकर अपना पैर गँवा बैठता तो शेष जीवन उसे बहुत कठिनाई से गुजारना पड़ता था। इसपर उपाय के रूप में डॉ. प्रमोद सेठी ने कुशल कारीगर रामचंद्र शर्मा की सहायता से कृत्रिम हाथ, पैर, नाक, कान तैयार किए।

जयपुर फुट तकनीकी के उपयोग से तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर, ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना जैसे काम सहजता के साथ कर सकता है। इस कृत्रिम पैर में जूता पहनने की आवश्यकता न होने से जूते का खर्च बचता है। पैर मोड़ना एवं पालथी मारकर बैठना कृत्रिम पैर के कारण संभव हो गया है। पानी में तथा गीली अवस्था में काम करने के लिए ये पैर सुविधाजनक होते हैं।

मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (किडनी ट्रान्सप्लांट) : यह शल्यक्रिया भारत में साध्य हो जाने से रोगियों के प्राण बचाने में डॉक्टरों को सफलता मिली है। वर्ष १९७१ से पूर्व इस तरह की शल्यक्रियाएँ भारत में बहुत-अधिक नहीं होती थीं। तमिलनाडु के वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में यह शल्यक्रिया वर्ष १९७१ में सफल

हुई। डॉ. जॉनी व डॉ. मोहन राव ने जीवित व्यक्ति द्‌वारा दान किए गए मूत्रपिंड का रोगी के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। अब अविकसित देशों के रोगी यह शल्यक्रिया करवाने के लिए भारत में आते हैं।

टेस्ट ट्यूब बेबी : भारत में पहले से ही परिवार व्यवस्था में संतान का होना महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है। संतान की इच्छा रखने वाले पति-पत्नी को संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष १९७८ से 'टेस्ट ट्यूब बेबी' इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हो गया। कोलकाता में डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय की देख-रेख में 'टेस्ट ट्यूब बेबी' का प्रयोग सफल रहा। कृत्रिम गर्भधारणा तकनीक का यह प्रथम प्रयोग सफल रहा। इस तकनीकी के माध्यम से 'दुर्गा' नामक की बच्ची का जन्म हुआ। इस कारण संतान की इच्छा रखने वाले अभिभावकों की समस्या हल होने में सहायता मिली।

टीकाकरण : वर्ष १९७८ से पूर्व भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले दस बच्चों में से छह बच्चे जन्म के बाद पहले ही वर्ष में प्राणघाती बीमारियों की चपेटे में आ जाते थे। पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलगंड और कुकुरखाँसी जैसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। वर्ष १९९५ में 'पल्स पोलियो' टीकाकरण अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप पोलियो की रोक-थाम की जा सकी।

शहरीकरण :

शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जनबस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्त्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में मृत्यु दर का घटना, औद्‌योगीकरण, ग्रामीण भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार, स्थलांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्‌धि के प्रमुख कारण हैं।

शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे-छोटे गाँवों में रोजगार उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों की होने वाली वृद्‌धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध करवाना जैसे उपाय हैं।

ग्रामीण भाग

स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गाँव कहते हैं। कृषि की खोज किए जाने पर गाँव अस्तित्व में आए। भारत की देहात पद्‌धति विरल जनबस्ती की पद्‌धति है। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में वह काफी छोटा गुट होता है। गाँव से छोटा गुट बस्ती है।

संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं है। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है।

स्वातंत्र्योत्तर कालखंड : ग्रामविकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ की गई। उसके माध्यम से कृषि तकनीक को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना उद्‌देश्य था। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये कार्य आरंभ किए। ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों-जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई। इसके लिए ग्रामपंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए।

बदलता आर्थिक जीवन : पहले ग्रामीण जीवन आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था। गाँव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। कारीगरों को उनके काम के मेहनताने के रूप में कृषि उत्पादन बाँट दिया जाता था। अब यह परिस्थिति बदल चुकी है। ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि संबधी पूरक धंधों से जोड़ा गया है, तो नगरीय समाज कृषितर उत्पादन व सेवा व्यवसायों से जुड़ गया है।

ग्रामीण विकास : भारत में वर्ष १९६१ में ८२% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे तो १९७१ में यह अनुपात ८०.१ % था। अनाज एवं अन्य कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरतों को पूरा करना, शहर के औद्योगिक विभागों को श्रमिकों की आपूर्ति करना, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तक करता आया है। इस कारण आर्थिक व्यवसायों का विकास करना, सामाजिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का विकास करना, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ये तीन महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ ग्रामीण विकास के संदर्भ में हैं। भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान करना आवश्यक है।

सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा : सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की ओर प्रधानता क्रम से ध्यान देना आवश्यक है। पेयजल की बारहोंमासी सुविधा, स्वच्छतागृह, बंद नालियाँ, सँकरी सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, औषधोपचार की असुविधा जैसी समस्याओं से ग्रामीण भाग आज भी घिरा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक स्तरीय सुविधा की उपलब्धता का अभाव, मनोरंजन केंद्रों एवं वाचनालयों की संख्या कम होने कारण ग्रामीण भाग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत की प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में समूह विकास योजना को महत्त्वपूर्ण स्थान था। महाराष्ट्र राज्य ने इस योजना के अंतर्गत प्रभावशाली काम किया है। महाराष्ट्र में वर्ष १९६२ में जिला परिषदों की स्थापना की गई। वर्ष १९७०-७१ में महाराष्ट्र में सकस आहार (पौष्टिक भोजन) योजना शुरू की गई। कुएँ खोदना एवं नलों द्वारा जलापूर्ति करना; इसके लिए 'ग्रामीण जलापूर्ति योजना' शुरू की गई। वर्ष १९७१ के अंत में १६७७ लघु बाँध परियोजनाओं के काम पूर्ण किए गए।

ग्रामीण विद्युतीकरण : ग्रामीण भाग में विकास हेतु बिजली की नितांत आवश्यकता होती है। कृषि में जलापूर्ति हेतु स्वचलित पंप लगते हैं। दूध एवं अंडे जैसे नाशवान पदार्थ टिकाए रखना, फल एवं शाक-सब्जी टिकाए रखना, खाद परियोजना चलाना, विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु रात में बिजली का होना, पंखा, दूरदर्शन जैसे यंत्रों के लिए बिजली लगती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में तीन हजार देहातों में विद्युतीकरण किया गया। वर्ष १९७३

वैश्वीकरण से पूर्व के समय में ग्रामीण व नगरीय समाज

ग्रामीण समुदाय	नगरीय समुदाय
कृषि एवं संलग्न धंधों को वरीयता।	कृषितर उत्पादन एवं सेवा व्यवसायों को वरीयता।
छोटा आकार, भाषा संस्कृति व परंपरा एकविधि।	बड़ा आकार, भाषा, संस्कृति तथा परंपरा बहुविधि।
प्राथमिक स्वरूप का व्यवसाय, बाहरी लोगों को ग्रामीण व्यवसाय में समाहित करने की बजाय गाँव से उन्हें शहर भेजनेवाला।	बड़े-बड़े व्यवसाय तथा विश्वस्तर के लिए उत्पादन। अन्य भागों से आने वालों को समाहित करने वाला।
अनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा अधिक।	अनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा दोयम।
परिवार प्रमुख एवं परिवार व्यवस्था को वरीयता संयुक्त परिवार पद्धति।	परिवार को दोयम स्थान। व्यक्ति को वरीयता। संयुक्त परिवार पद्धति का विघटन।

में यह संख्या १,३८,६४६ देहातों तक पहुँच गई। वर्ष १९६६ से पंप एवं नलकूपों को अधिक बिजली देने की योजना बनाई गई। वर्ष १९६९ में 'ग्रामीण विद्युतीकरण निगम' स्थापित किया गया। इसी से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाएँ अस्तित्व में आईं।

औद्योगिक विकास : ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु 'ग्रामोद्योग नियोजन समिति' की स्थापना की गई। वर्ष १९७२ के अंत तक इस योजना में एक लाख छह हजार लोगों को रोजगार मिला।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले विशेष बुद्धिमान विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सातारा, औरंगाबाद, नाशिक एवं चिखलदरा में विद्या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्यालय आरंभ किए। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी, अकोला, परभणी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्यालय शुरू किए गए। महाराष्ट्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष १९७२ में साक्षरता प्रसार गौरव का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान दिया।

इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर समय के आरंभ में उत्पन्न हुईं बाधाओं को पार करते हुए भारत ने विकास का लक्ष्य साधने की शुरुआत की। अगले पाठ में हम अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) डॉ. एन. गोपीनाथ के नेतृत्व में भारत के ..... शहर में पहली ओपन हार्ट सर्जरी सफल हुई।
(अ) चेन्नई (ब) वेल्लूर
(क) हैदराबाद (ड) मुंबई

(२) 'जयपुर फुट' के जनक के रूप में .....को पहचाना जाता है।
(अ) डॉ. एन. गोपीनाथ
(ब) डॉ. प्रमोद सेठी
(क) डॉ. मोहन राव
(ड) इनमें से कोई नहीं

२. निम्नलिखित में से असंगत जोड़ी को पहचानिए एवं लिखिए।

(१) डॉ. एन. गोपीनाथ - ओपन हार्ट शिल्पकार
(२) रामचंद्र शर्मा - कुशल कारीगर
(३) डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय - टेस्ट ट्यूब बेबी
(४) डॉ. मोहन राव - पोलियो

३. टिप्पणी लिखिए।

(१) परिवार संस्था (२) जयपुर फुट तकनीक
(३) शहरीकरण (४) बदलता आर्थिक जीवन

४. निम्नलिखित कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया।
(२) ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई।

५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए।

(१) संविधान के अनुसार किन बातों के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है?
(२) समाज कल्याण कार्यक्रम के कौन-से उद्देश्य हैं?
(३) ग्रामीण विकास के संदर्भ में कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

६. सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में हुई मुख्य गतिविधियों की संक्षेप में समीक्षा कीजिए।

उपक्रम

आपके परिसर के किसी वरिष्ठ/ बुजुर्ग व्यक्ति से निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर साक्षात्कार कीजिए।
- घरों की रचना में हुए परिवर्तन।
- कृषि के संदर्भ में हुए परिवर्तन।
- वाहनों की उपलब्धता।

7HCEPL